(ख) क्या ललितपुर रेलवे स्टेशन के उस पार 5000 लोगों की एक बस्ती है और कई रेलवे क्वार्टर बने हुए हैं तथा क्या मालगाड़ी व अन्य गाड़ियां खड़ी होने के कारण लोगों को लाइन पार करने के लिए बड़ी परेशानी का अनुभव करना पड़ता है और क्या कुछ दुर्घटनायें भी हुई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूरा पुल बनाने का है जिससे लोगों को ललितपुर स्टेशन तथा ललितपुर शहर को आने जाने में असुविधा न हो ?

**रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण)** : (क) ललितपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूदा ऊपरी पैदल पुल जो अप और डाउन द्वीप प्लेट फार्मों को मुख्य प्लेट फार्म और स्टेशन इमारत से मिलाता है, केवल सदाशयी रेल यात्रियों के उपयोग के लिए है। यह पुल यार्ड में सभी रेल पथों के ऊपर नहीं है।

(ख) स्टेशन की पश्चिमी ओर पिछले 10 वर्षों के दौरान एक बस्ती बस गई है, स्टेशन के उसी ओर लगभग 50 रेलवे क्वार्टर भी हैं। जनता रेल पथों को पार करने के लिए स्टेशन की बम्बई दिशा में स्थित 'ग' वर्ग के समपार का सुविधापूर्वक उपयोग कर सकती है। निकट अतीत में यहां किसी भी घटना के होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान नियमों के अनुसार, जनता द्वारा रेल पथों को पार करने के लिए नए ऊपरी पदल पुलों के निर्माण अथवा वर्तमान ऊपरी पुलों के विस्तार की पूरी लागत राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन करनी होती है। यदि इस सम्बन्ध में राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्रस्ताव प्रायोजित होता है और वे उसकी लागत वहन करने का वचन देते हैं, तो इस बारे में कार्यवाही की जाएगी।

### New Distribution System of L.P. Gas

1239. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government has recently approved any new distribution system for the supply of liquified petroleum gas (LPG) by Indian Oil to some of the dealers; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). According to the guidelines now evolved, the ceilings on the number of refills of cylinder that an LPG distributor of any company including that of Indian Oil Corporation, would be allowed to handle per month have been fixed as follows, after taking into account the different working conditions and cost of operation in different areas:

| Market | Number of refills per month |
|---|---|
| Bombay . | 6,000 |
| Delhi . . . . | 4,000 |
| Other cities with population over 10 lakhs . . . . | [illegible],500 |
| Cities with population between 2 lakhs and 10 lakhs . . | 3,000 |
| Other places . . | 2,500 |

The Co-operative Societies would be exempted from these ceilings.

### L-Base Licence to M/s. Boehringer Knoll Ltd.

1240. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is true that M/s Boehringer Knoll Ltd., had received

L-base under REP policy during 1976-77 and 1977-78;

(b) whether they are licensed to manufacture Chloramphenicol from intermediate stages; and

(c) if not, what action Government propose to take for such a violation of the industrial licence?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) M/s. Boehringer Knoll Ltd. have reported that they procured 5700 kgs of L-Base during 1976-77 but they did not procure any quantity of this material during 1977-78.

(b) No, Sir.

(c) This matter came to the notice of Govt. very recently. The company are being asked to explain the circumstances in which they used imported L-Base for the manufacture of Chloramphenicol.

### कानूनी व्यवस्था में सुधार

1241. श्री पुखराज : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब लोगों के साथ हो रहे भेदभाव पूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी व्यवस्था में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या न्यायाधीश तथा वकील मुआवजे के भुगतान तथा छंटनी आदि से बचने के लिए श्रम-कानूनों के विरुद्ध अमीर लोगों द्वारा दी जाने वाली दलीलों की बारीकियों तथा प्रभावों में अधिक रुचि लेते हैं तथा उन्हें समझते हैं तथा उनमें रुचि लेते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कानूनी व्यवस्था में सुधार कब तक किये जायेंगे और यदि कोई सुधार नहीं किया जाना है तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### Over Invoicing and Under Invoicing by Drug Firms

1242. SHRI RATAN SINH RAJDA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Wyeth Laboratories Abbot Laboratories, Roche Products, Borroughs Wellcome, May and Baker and other companies having more than 26 per cent foreign equity indulge in over-invoicing and under-invoicing with a view to repatriate moneys to their parent companies through this indirect means;

(b) whether any such practice has come to the notice of Government; and

(c) if not, will Government scrutinise the prices at which these companies have imported raw materials and the prices at which they are available in the international markets?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c). No instances of over-invoicing and under-invoicing by companies having foreign equity of more than 26 per cent have come to the notice of the Government. The prices of raw materials imported by companies do vary depending upon several factors including the source of import. If any specific instances are brought to the notice of the Government, they would be looked into.

### Production of Natural Gas

1243. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether we are producing Natural gas in our country; and